

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ० प्र०) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय/ महोदया,

विषय :- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की सितम्बर 2021 त्रैमासांत की समीक्षा हेतु सम्पन्न वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक दिनांक 31.12.2021 का कार्यवृत्त

कृपया दिनांक 31.12.2021 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ० प्र०) की सितम्बर 2021 त्रैमासांत की समीक्षा बैठक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था।

उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,



(ब्रजेश कुमार सिंह)

महाप्रबन्धक एवं संयोजक

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की सितम्बर 2021 तिमाही की दिनांक
31.12.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की सितम्बर 2021 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 31.12.2021 को आयोजित की गयी। कोरोना महामारी के नए वैरिएंट (Omicron) के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत इस बैठक का आयोजन पूर्ण रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। बैठक की अध्यक्षता श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी। इस बैठक में श्री आर. लक्ष्मीकांत राव, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ; प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी श्री प्रदीप कुमार, आई.ए.एस., विशेष सचिव, एम.एस.एम.ई., उ०प्र० शासन; श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ०प्र०; श्रीमती गीता सिंह, उप महाप्रबंधक, नाबार्ड, लखनऊ सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा सहभागिता की गयी। बैठक में भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में श्री ब्रजेश कुमार सिंह, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ०प्र० ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। अपने स्वागत सम्बोधन में बैंकों द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग व कार्यों की सराहना की। उन्होंने प्रदेश में की जा रही बैंकिंग गतिविधियों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों की अद्यतन प्रगति से सभा को अवगत कराया।

गत बैठक दिनांक 11.08.2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि के उपरांत उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण मानकों पर प्रदेश की स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्नवत प्रस्तुत किया:-

1. सितम्बर 2021 को समाप्त तिमाही तक प्रदेश का कुल कुल व्यवसाय ₹ 1980712 करोड़ है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश के बैंकिंग व्यवसाय में कुल ₹ 38157 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गयी है। कुल व्यवसाय में जमा ₹ 1313815 करोड़ रहा है जो जून 2021 (₹ 1280745 करोड़) के तुलना में ₹ 33070 करोड़ बढ़ा है। साथ ही सितम्बर 2021 में कुल अग्रिम ₹ 666897 करोड़ रहा है जिसमें जून 2021 (₹ 661810 करोड़) के स्तर से ₹ 5087 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है।
2. प्रदेश में ऋण जमानुपात हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के मानक 40% से कम ऋण जमानुपात वाले जनपदों की संख्या जून 2021 में 9 जनपदों से घटकर सितम्बर 2021 में 8 हो गयी है।
3. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक प्रदेश में Credit Outreach कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रदेश के समस्त जनपदों में 15000 से अधिक ऋण शिविरो के माध्यम से ₹. 10 हजार करोड़ से अधिक का ऋण स्वीकृत किया गया।
4. चालू वित्तीय वर्ष हेतु वार्षिक ऋण योजनांतर्गत आवंटित लक्ष्य ₹ 279794 करोड़ के सापेक्ष ₹ 104452 करोड़ का ऋण वितरण करते हुए 37.33% की उपलब्धि हासिल की गयी है। हमारे प्रदेश में MSME Sector के अन्तर्गत कुल आवंटित लक्ष्य ₹ 72251 करोड़ के सापेक्ष ₹ 45198 करोड़ का ऋण वितरण करते हुए 62.96% की उपलब्धि हासिल की गयी है। साथ ही कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कुल आवंटित लक्ष्य ₹. 180541 के सापेक्ष ₹ 55625 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है जो 30.81% की उपलब्धि दर्शाता है।

5. प्रदेश में बैंकों के कुल अग्रिम के सापेक्ष प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ₹ 3.87 लाख करोड़ (57%), MSME क्षेत्र में ₹ 1.40 लाख करोड़ (21%) व कमज़ोर वर्ग में ₹ 1.27 लाख करोड़ (19%) अग्रिम रहा है जो RBI के निर्धारित मानक क्रमशः 40%, 20% व 10% से अधिक है।
6. प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्रदेश में अभी तक 7.57 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जिसमें से वित्तीय वर्ष 2021-22 की द्वितीय तिमाही के दौरान कुल 44 लाख नये जन धन खाते खोले गये हैं।
7. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार प्रदेश में टियर -6 केंद्रों (5000 से कम जनसंख्या वाले केंद्रों) पर मौजूद बैंकिंग आउटलेट की सूचना का संकलन किया जा रहा है ताकि बैंकिंग सुविधाओं के और अधिक विस्तार हेतु रोडमैप तैयार किया जा सके।
8. सितम्बर 2021 तिमाही के दौरान 34 लाख नये नामांकन करते हुए सामाजिक सुरक्षा योजना यथा PMJJBY और PMSBY के तहत कुल 4.29 करोड़ नामांकन किए जा चुके हैं। योजना के तहत लोगों को कवर करने के लिए अभी भी बड़ा स्कोप उपलब्ध है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 51.07 लाख नामांकन किये जा चुके हैं।
9. PMSVANidhi योजनान्तर्गत हमारा प्रदेश कुल स्वीकृत आवेदन पत्र (8.43 लाख), वितरण (7.50) के मामले में PAN INDIA प्रथम स्थान पर है जिसकी सराहना भारत सरकार व विभिन्न स्तरों पर भी की गयी है।
10. सरकार प्रायोजित विभिन्न रोज़गारपरक योजनाओं के वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति करने हेतु मैं समस्त बैंकों का आह्वान करता हूँ।
11. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार प्रदेश में डिजिटल मोड से संतृप्त करने हेतु प्रथम चरण में चिन्हित दोनो जनपदों यथा सिद्धार्थनगर तथा फिरोज़ाबाद में सफलता प्राप्त होने के भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्येक राज्य में 1 या 2 नये जनपदों को कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में हमारे प्रदेश के -2- नये जनपदों यथा सीतापुर (इण्डियन बैंक ऑफ इंडिया) व मुरादाबाद (केनरा बैंक) को 1 वर्ष की अवधि (सितम्बर 2022 तक) में डिजिटल मोड से संतृप्त करने हेतु चिन्हित किया गया है। इस कार्यक्रम की नियमित समीक्षा एस.एल.बी.सी. की उप-समिति में की जा रही है। निश्चय ही समस्त बैंकों के समग्र प्रयास से हम इस लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकेंगे।
(कार्यावाही: सम्बन्धित जनपदों में कार्यरत समस्त बैंक, इण्डियन बैंक, केनरा बैंक (संयोजक: विषय पर गठित उप-समिति)
12. हमें प्रदेश सरकार द्वारा RC Filed cases में Recovery हेतु निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहता है। एक बार पुनः मैं प्रदेश सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरफेसी के अंतर्गत लम्बित मामलों में वसूली हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

अंत में उन्होंने पुनः समस्त सहभागियों का धन्यवाद व्यक्त किया।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री विक्रमादित्य सिंह खींची, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभा में उपस्थित समस्त सम्मानित सदस्यों का अभिवादन करते हुये देश एवं प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों तथा विभिन्न मानकों में प्रदेश में हुई प्रगति से सभा को अवगत कराया तथा उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला:

- 1) प्रदेश का ऋण जमानुपात सितम्बर 2021 को समाप्त तिमाही में 52% के स्तर पर बना हुआ है। विगत चार वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश के ऋण जमानुपात में 6 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि हुई है। निश्चय ही आने वाले समय में प्रदेश का ऋण जमानुपात आपेक्षित स्तर तक पहुँचने में सफल होगा।

- 2) प्रदेश में वित्तीय समावेशन विस्तार की पर्याप्त सम्भावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार के "One GP One BC योजना" के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 58 हजार बी.सी. सखी रखने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख राज्य बन गया है।
- 3) अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 51 लाख से अधिक लोगो को नामांकित किया जा चुका है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में सितंबर 2021 तिमाही तक कुल 7.06 लाख नये लोगों को जोड़ा गया है। गर्व का विषय है कि PFRDA द्वारा SLBC(U.P) को विगत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए को "AWARD OF PAR EXCELLENCE" से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के -62- जनपदों को "CERTIFICATE OF EXCELLENCE" से सम्मानित किया गया है। मैं इसके लिये अपने सभी बैंकर्स साथियों को बधाई देता हूँ।
- 4) जनसुरक्षा योजनाओं यथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उत्कृष्ट कार्य किया गया है जिसके फलस्वरूप इन योजनाओं में प्रदेश पूरे भारत वर्ष में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर है, जो एक गर्व का विषय है।
- 5) बैंकों द्वारा सितंबर 2021 तक डिजीटल माध्यम से लेन-देन के कुल 186 Crore Transactions किये जा चुके हैं जो गत वर्ष की समान अवधि में किये गये कुल Transactions (176 crore) की तुलना में लगभग 10 करोड़ (याने 6%) अधिक हैं। प्रदेश में Digital लेनदेन में निरंतर प्रगति दर्ज हुई है जो सराहनीय है।
- 6) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों (MSME) को बढ़ावा देने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में एक नया रिकार्ड बना रहा है। प्रदेश के हर जिले में नई-नई MSME इकाइयों की स्थापना हो रही है। कोरोना के वैश्विक संकट के दौरान भी इस सेक्टर में करीब डेढ़ लाख नई इकाइयां लगाई गई है। विभिन्न बैंकों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष सितंबर तक डेढ़ लाख से अधिक लोगों को रुपए 11702 करोड़ का लोन दिया गया है।
- 7) प्रधानमंत्री मुद्रा योजनान्तर्गत प्रदेश ने गत 4 वर्षों से निरंतर निर्धारित लक्ष्यों को पार किया है। सितंबर 2021 तिमाही के दौरान योजना के अंतर्गत लगभग 9.32 लाख उद्यमियों को रु. 5814 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की गयी है।
- 8) यद्यपि उत्तर प्रदेश में पी.एम. स्वनिधि योजनान्तर्गत देश में सर्वाधिक ऋण वितरण किया गया है, परन्तु योजनान्तर्गत निस्तारण व वितरण हेतु लम्बित क्रमशः 74730 व 92451 आवेदनों की संख्या भी प्रदेश में अधिकतम है जो चिंता का कारण है। समस्त बैंकों से अनुरोध है कि इन आवेदनों के अविलम्ब निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
(कार्यवाही: समस्त बैंक)
- 9) प्रदेश के -11- जनपदों में आरसेटी हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया लम्बी अवधि से लम्बित है। प्रदेश शासन से अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करे ताकि इन संस्थानों के माध्यम से अधिकाधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके।

(कार्यवाही: संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ०प्र०)

- 10) SARFAESI Act के अंतर्गत सभी बैंकों के -5,208- मामले प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिलाधिकारी कार्यालय में आवश्यक अनुमति हेतु लम्बित है जिनमें से -3,844- मामले -60- दिन की अवधि से अधिक समय से लम्बित है। हालांकि प्रदेश सरकार द्वारा गत माहों में किये गये प्रयासों व अनुश्रवण के कारण जनपद स्तर पर गतिशीलता प्रदर्शित हुई है, लंबित आर.सी. की वसूली हेतु भी राज्य सरकार का सहयोग अपेक्षित है एवं मुझे आशा है कि इसके लिए राजस्व परिषद विभाग द्वारा निर्मित पोर्टल प्रभावी सिद्ध होगा।

(कार्यवाही: एम.एस.एम.ई. विभाग, उ०प्र० / संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ)

अंत में उन्होंने प्रदेश शासन के शीर्ष अधिकारियों तथा सभा में मौजूद सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी एवं गरिमामयी उपस्थिति हेतु आभार व्यक्त किया तथा कोरोना महामारी के दृष्टिगत आवश्यक सावधानी बरतने हेतु अनुरोध किया।

श्री आर. लक्ष्मीकांत राव जी, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभा में उपस्थित अन्य अधिकारीगणों का अभिवादन करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:-

➤ उन्होंने बताया कि प्रदेश में बैंक शाखाओं, व बैंक मित्रों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से समस्त केन्द्रों की 5 कि.मी. की परिधि में बैंकिंग आउटलेट की स्थापना पूर्ण की जा चुकी है। साथ ही प्रदेश में बी.सी. सखी की नियुक्ति के साथ बैंक सुविधाओं की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी है।

➤ उन्होंने बताया कि बैंकों में निष्क्रीय खातों व निष्क्रीय बैंक मित्रों को सक्रिय करने हेतु सम्बन्धित बैंकों द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही वित्तीय समावेशन के अन्य उत्पादों जैसे माइक्रो इश्योरेंस आदि तथा बैंक खातों में अधिकाधिक ट्रांजैक्शन को भी बैंकों द्वारा बढ़ावा दिए जाने हेतु आवश्यक प्रयास किये जाने चाहिए।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

➤ भारतीय रिज़र्व बैंक की National Strategy for Financial Inclusion (NSFI) 2019-2024 के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए प्रत्येक खाते को कम से कम एक जनसुरक्षा योजना से कवर करने का लक्ष्य रखा गया। प्रदेश में जनसुरक्षा योजनाओं से कवर करने हेतु खातों में अभी भी अपार संभावनाएं मौजूदा हैं। अतः बैंकों द्वारा इस दिशा में वांछित प्रयास किये जाने अपेक्षित है।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

➤ उन्होंने बैंकों द्वारा एम.एस.एम.ई. इकाइयों, विशेषकर मध्यम श्रेणी की इकाइयों को TReDS प्लेटफॉर्म पर आने हेतु प्रेरित करने का अनुरोध किया ताकि इन इकाइयों द्वारा इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया जा सके।

➤ वित्तीय वर्ष 2021-22 की सितम्बर 2021 तिमाही अंत तक वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत कृषि क्षेत्र हेतु आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष लगभग 30% उपलब्धि हासिल की गयी है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है अतः बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र विशेषकर एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर व टर्म लोन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

➤ बड़ी संख्या में लम्बित आर.सी. के मामले निश्चय ही एक चिंता का कारण है। कुल लम्बित आर.सी. मामलों में से लगभग 70% मामलों एक वर्ष से अधिक की अवधि से लम्बित है। इस हेतु उन्होंने बैंकों से अपने प्रयासों को बढ़ाने तथा प्रदेश शासन से बैंकों को वांछित सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया।

➤ उन्होंने सभा को अवगत कराया कि आगामी लोक सभा के चुनावों की तैयारी समीक्षा हेतु दिनांक 28.12.2021 को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें चुनाव के दौरान बैंकिंग प्रणाली के दुरुपयोग व नकदी के आवागमन हेतु विशेष सावधानी बरतने तथा इसा हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंकर्स संघ व निर्वाचन आयोग के मौजूदा दिशा-निर्देशों के कड़ाई से अनुपालना करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

अपने संबोधन के अंत में उन्होंने सभा में उपस्थित समस्त सहभागियों व समस्त बैंकर्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी।

श्री प्रदीप कुमार, आई.ए.एस., विशेष सचिव, एम.एस.एम.ई., उ0प्र0 शासन ने सभी सहभागियों का अभिवादन करते हुए समस्त बैंकों से प्रदेश में एम.एस.एम.ई. सम्बन्धित समस्त सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लम्बित आवेदनों को शीघ्रताशीघ्र निस्तारित करने हेतु निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने लम्बित आर.सी. के निस्तारण हेतु प्रदेश शासन की ओर से बैंकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया।

(कार्यवाही: समस्त बैंक)

श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ ने अपने संबोधन में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ०प्र०) तथा प्रदेश के समस्त बैंको को प्रदेश में आयोजित क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम (16 अक्टूबर से 30 नवम्बर, 2021) में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु बधाई दी तथा प्रदेश का कुल व्यवसाय लगभग रूपये 20 लाख करोड़ तक पहुंचाने हेतु सराहना की।

उन्होंने समस्त बैंकर्स से प्रदेश के समस्त जनपदों का ऋण जमानुपात भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित मानक 40% तक पहुंचाने तथा वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि हेतु समग्र प्रयास करने की अपेक्षा की।

उन्होंने समस्त बैंको से सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनान्तर्गत लम्बित आवेदनों के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया। प्रदेश के समस्त जनपदों में नियमित रूप से डी.सी.सी. व बी.एल.बी.सी. के आयोजन की महत्ता पर उन्होंने बल दिया। साथ ही उन्होंने 11 जनपदों में आरसेटी हेतु लम्बित भूमि आवंटन तथा लम्बित आर.सी. के प्रकरण में शासन की ओर से पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु आश्वस्त किया।

श्रीमती गीता सिंह, उप महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने अपने संबोधन में प्रदेश में एफ.पी.ओ. की भाँति स्वयं सहायता समूहों को भी 4% ब्याज उपादान प्रदान करने के विषय पर सहभागियों का ध्यानाकर्षण किया ताकि स्वयं सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज को बढ़ावा मिले।

साथ ही उन्होंने बताया प्रदेश में दुग्ध तथा मत्स्य पालक कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में साप्ताहिक कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की निरंतर उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही परन्तु अभी अपेक्षित प्रगति हासिल नहीं हो रही है। अतः बैंकों द्वारा इस दिशा में और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। (कार्यवाही: समस्त बैंक)

सभी गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के पश्चात सभा के समक्ष पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दी गयी जिसमें निम्न बिन्दु सामने आए:-

- 1) मत्स्य एवं डेयरी कृषकों को के.सी.सी. प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे साप्ताहिक जनपद स्तरीय के.सी.सी. कैम्प के अंतर्गत प्रदेश में बैंको के स्तर पर 15 दिनों से अधिक लम्बित समस्त आवेदन पत्रों को यथाशीघ्र निस्तारित करने हेतु समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया। (कार्यवाही : समस्त बैंक)
- 2) डिजिटल माध्यम से कवर करने हेतु चिन्हित -2- जनपदों यथा सीतापुर व मुरादाबाद में सितम्बर 2021 तक बचत खातों में क्रमशः 78.12% व 27.98% तथा चालू खाते में क्रमशः 68.26% व 43.90% का कवरेज प्राप्त किया गया है।
- 3) प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत रुपये 334.35 करोड़ मार्जिन मनी के निर्धारित वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 की सितम्बर 2021 तिमाही तक रु.302.02 करोड़ स्वीकृत तथा रु. 210.82 करोड़ का वितरण किया गया है।
- 4) लखनऊ और वाराणसी में क्रमशः दिनांक 22.11.2021 और 23.11.2021 को मेगा क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किये गए हैं, जिसमें डॉ भागवत कराड, माननीय वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान रु. 398 करोड़ और रु. 276 करोड़ का सभी बैंकों द्वारा क्रमशः ऋण स्वीकृत व वितरण किया गया है।

बैठक के अंत में श्री शंभू लाल, महाप्रबन्धक, केनरा बैंक, लखनऊ द्वारा प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों तथा अन्य समस्त सहभागियों का आभार व्यक्त किया जिनके सहयोग से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक संपन्न की जा सकी। साथ ही उन्होंने समस्त सहभागियों को नव वर्ष हेतु हार्दिक शुभकामनाएं दी।
